Page Three

Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment
Property
Business Opportunity
Vehicles
Announcements
Antiques & Collectables
Barter
Books
Computers
Domain Names
Education
Miscellaneous
Entertainment & Event
Hobbies & Interests
Services
Jewellery & Watches
Music
Obituary
Pets & Animals
Retail
Sales & Bargains
Health & Sports
Travel

Matrimonial (Sunday Only)

अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

अंतिम दिन सदन के पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट

शीतकालीन सत्र

कैग की रिपोर्ट में कई वित्तीय अनियमिताएं उजागर

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। कैग की रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय सेहत के अत्यन्त खराब होने की बात कही गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार को आने वाले समय में लिए गये कर्ज का ब्याज तक चुकाना मुश्किल हो जायेगा। रिपोर्ट में घटती राजस्व प्राप्तियों व बढ़ते वित्तीय घाटे पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि यह स्थिति राज्य के भविष्य के लिए कतई अच्छी नहीं है। कैग की रिपोर्ट में कई वित्तीय अनियमिताएं उजागर की गई हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया विभिन्न कमियों से भरी थी। पेंशन डेटाबेस में इनपुट व वैलिडेशन कंट्रोल की कमी थी। जिससे 614 लाभार्थियों को 0.17 करोड़ के अधिक भुगतान के प्रकरण थे, मृत व्यक्तियों को 0.10 करोड़ का वितरण किया गया, अपात्र व्यक्तियों को 4.18 करोड़ का वितरण किया गया और 85 लाभार्थियों को 0.21 करोड़ का दोहरा भुगतान किया गया।

सरकार के सर पर 50 हजार करोड़ से अधिक का ऋण है जिसे चुकाने के लिए उसे हर साल 4 हजार 4 करोड़ रूपये चुकाने होगें। कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि लगातार बढ़ते वित्तीय घाटे और घटती राजस्व प्राप्तियों के कारण राज्य की वित्तीय सेहत दिनों दिन खराब होती जा रही है। अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो आने वाले समय में सरकार को उस ऋण का ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो जायेगा।

बैकिंग प्रबन्धन पर भी कैग द्वारा सवाल उठाये गये है साथ ही यह भी कहा गया है कि कई विभागों द्वारा कैग को आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये है। कैग की रिपोर्ट में जो कमियां इंगित की गई हैं उनमें उच्च शिक्षा विभाग से संबंद्ध राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर द्वारा 2.59 करोड़ के व्ययोपरांत अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं के लिए निर्मित छात्रावास की सुरक्षा एवं कर्मचारियों की कमी के कारण उपयोग नहीं किया जा सका और छात्रावास भवन जनवरी 2015 से अनुपयोगी पड़ा रहा।

गृह विभाग से संबद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों द्वारा निर्धारित दर पर प्रशमन शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण 3.17 करोड़ की राजस्व हानि हुई। सब्सिडी दिए जाने की शर्तों के उल्लंघन के प्रकरण में वसूली का प्रावधान है लेकिन उद्योग विभाग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी एक दोषी औद्योगिक इकाई से 49.56 लाख की वसूली करने में विफल रहा। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया विभिन्न कमियों से भरी थी। पेंशन डेटाबेस में इनपुट व वैलिडेशन कंट्रोल की कमी थी।

भारत सरकार से निधियों की कम मांग करने के कारण राज्य सरकार को 33.29 करोड़ का भार वहन करना पड़ा। अपात्र लाभार्थियों के लिए भारत सरकार से 7.25 करोड़ का अनियमित दावा किया गया। त्रैमासिक पेंशन किस्त के भुगतान में 366 दिनों तक के विलम्बित भुगान के प्रकरण थे। 34,551 लाभार्थियों को 15.25 करोड़ पेंशन एरियर का भुगान नहीं किया गया। योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया था। शिकायत निवारण और सामाजिक लेक्षा परीक्षा के लिए तंत्र भी लागू नहीं था।

वित्तीय प्रबन्धन पर गम्भीर सवाल

कैग की रिपोर्ट में राज्य सरकार के वित्तीय प्रबन्धन पर गम्भीर सवाल उठाये गये है तथा राज्य सरकार को अपनी आय के संसाधन बढ़ाने व खर्चे घटाने की हिदायत दी गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की अनुपातिक आय में लगातार कमी हो रही है जबकि खर्चो में वृद्धि हो रही है।

न्यूज डायरी

पेंशनर निर्धारित बचतों का विवरण जी. आर.डी नम्बर के साथ उपलब्ध कराएं

संवाददाता देहरादून। मुख्य कोषाधिकारी बी.एन. पाण्डेय ने बताया कि आयकर की धारा 161 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिये केवल साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेशनरों को आयकर आगणन हेतु इस वर्ष के लिये निर्धारित बचतों का विवरण अपने जी.आर.डी नम्बर को अंकित करते हुए सभी साक्ष्यों सहित चौप्टर के अनुसार तीन दिन के अन्दर मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून को छाया प्रति के साथ उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया कि बिना जी.आर.डी नम्बर के उक्त विवरण मान्य नहीं होगा तथा निर्धारित समय सीमा तक बचतों का विवरण उपलब्ध न होने की दशा में कार्यालय के अभिलेखानुसार आयकर आगणन कर आयकर की कटौती कर ली जायेगी।

अगवा मासूम पुलिस ने किया बरामद

संवाददाता रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में बहन के साथ खेल रहा मासूम शिवा सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। जिसे आज पुलिस ने बरामद कर लिया। उसके साथ ही पुलिस ने दो साल पहले किडनैप हुए शिवम को भी बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक पुरुष और तीन महिलाओं को अरेस्ट किया है। बता दें कि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में बहन के साथ खेल रहा मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजनों ने अपहरण का अंदेशा जताया तो पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी में दो लोग मासूम को ले जाते हुए कैद हुए तो पुलिस के हाथपांव फूल गए। आनन–फानन में अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करने के बाद पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई थी।

व्यापार मंडल का चुनाव 22 को, 755 मतदाता करेंगे मतदान

संवाददाता हल्द्वानी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रांतीय कार्यकारिणी के त्रिवार्षिक चुनाव के मद्देनजर चुनाव कार्यालय खोल दिया गया है। व्यापार मंडल संरक्षक बाबू लाल गुप्ता ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य चुनाव अधिकारी प्रमोद गोयल, चुनाव अधिकारी एनसी तिवारी व राजेश अग्रवाल समेत चुनाव संचालन समिति के सदस्यों ने मतदाता सूची प्रेषित की। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव में प्रदेश के 19 जिलों की 353 इकाइयों के कुल 799 मतदाता हिस्सा लेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 दिसंबर को किया जाएगा। इस क्रम में 15 को नामांकन प्रक्रिया, 16 को नाम वापसी तथा 22 दिसंबर को क्रिस्टल लान रामपुर रोड में मतदान होगा। उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

डीएवी में छात्र गुटों के बीच जमकर मारपीट

मारपीट

देहरादून। **(संवाददाता)**

डीएवी कालेज में आज एक बार फिर अध्यक्ष पद के निर्दलीय गुट और आर्यन संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच पुराने विवाद को लेकर बहस के बाद मारपीट हो गयी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर बीच बचाव किया। छात्र गुटों के बीच बीते रोज भी मारपीट की घटना हुई थी।

डीएवी कालेज में अध्यक्ष पद पर काबिज निर्दलीय गुट के कार्यकर्ता और आर्यन संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच गत रविवार को एक शादी समारोह में विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि इस विवाद में एक छात्र को जमकर चोटें आयी थी। इस प्रकरण के बाद बीते रोज जब एक बार फिर दोनों गुट आमने सामने आये तो उनमें फिर विवाद हो गया था। जिसे पुलिस ने बामुश्किल निपटाया।

मंगलवार को एक बार फिर छात्रों के दोनों गुट आमने सामने पड़ गये और उनमें फिर एक बार विवाद होना शुरू हुआ। जिसके बाद छात्रों के बीच जमकर लात घूंसे चले। इस बीच मामले की सूचना एक बार फिर पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंच कर स्थिति संभाली और छात्रों को हटाया गया।

मारपीट करते छात्रों को काबू करती पुलिस।

नैनी झीलः जल स्तर छह फीट नीचे पहुंचा

नैनी झील।

संवाददाता नैनीताल। इस बार अब तक पर्याप्त वर्षा व बर्फवारी नहीं होने व लाखों लीटर पानी जलागम क्षेत्रों से दोहन करने के बाद जीवनदायिनी नैनी झील लगातार खतरे की ओर बढ़ रही है। एक ओर नैनी झील का जल स्तर लगातार गिर रहा है। दूसरी ओर झील के जलागम क्षेत्रों से भूमिगत जल 11 नलकूपों से आठ लाख लीटर पानी रोजाना लगातार दोहन किया जा रहा है। यह सिलसिला पिछले तीन–चार वर्षों से लगातार चल रहा है लेकिन शासन प्रशासन महज चिन्ता ही प्रकट कर रहा है। जमीनी योजनाएं कहीं नहीं दिख रही है। तेजी से घट रहे जलस्तर नैनीताल के लिए सर्वाधिक चिन्ता का विषय बना हुआ है।

जाट समाज ने फिल्म पानीपत का किया विरोध

संवाददाता रुड़की। फिल्म पानीपत के विरोध में जाट समाज सेवा समिति ने धरना–प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। जाट समाज सेवा समिति के पदाधिकारी मंगलवार को तहसील स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए।

फिल्म पानीपत का विरोध करते हुए समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि फिल्म पानीपत में जाट समाज के आदर्श महाराज सूरजमल के चरित्र को गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। उनके चरित्र और इतिहास के साथ फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की ओर से छेड़छाड़ की गई है। इसे जाट समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। नितिन चौधरी ने कहा कि फिल्म में महाराज सूरजमल का चित्रण मनगढ़ंत तरीके से करना अशोभनीय है। इससे जाट समाज में पूरा रोष है।

नागरिक संशोधन बिल के विरोध में भाकपा (माले) ने किया प्रदर्शन

संवाददाता

हल्द्वानी। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर भाकपा (माले) द्वारा घोषित राष्ट्रीय प्रतिवाद दिवस पर बुद्धपार्क में आयोजित धरना–प्रदर्शन को संबोधित करते हुए माले राज्य सचिव कामरेड राजा बहुगुणा ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल भारत के धर्मनिरपेक्ष बहुलतावादी संविधान को खत्म करने की साजिश है, ताकि आरएसएस अपने सवर्ण हिन्दुत्ववादी–मनुवादी समाज व्यवस्था को लागू करवा सके। जोकि एक तानाशाही राज्य की अवधारणा है।

सभा को संबोधित करते हुये माले जिला सचिव डॉ. कैलाश पाण्डेय ने कहा कि अगर शरणार्थियों को शरण देने की ही बात है तो मोदी सरकार शरणार्थियों को धर्म के आधार पर क्यों बांट रही है। केवल उन्हीं तीन देशों को क्यों चुना गया है जो मुस्लिम बहुल हैं। किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनन्द सिंह नेगी ने कहा कि जेएनयू, डीयू और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में फीस वृद्धि के खिलाफ चल रहे आंदोलनों पर दमन और हमला शिक्षा के निजीकरण की ओर धकेलने का कदम है। धरने में मुख्य रूप से माले की केंद्रीय कमेटी के सदस्य संजय शर्मा, वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जंगी, अम्बेडकर मिशन के अध्यक्ष जीआर टम्टा, भुवन जोशी, आनन्द सिंह सिजवाली, गोविंद जीना, स्वरूप सिंह दानू, नैन सिंह कोरंगा, गिरीश जोशी आदि बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।

धरना देते भाकपा माले के कार्यकर्ता।